

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

प्रलम्ब के लिये:

[प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ](#), मॉडल उपनयम, सहकारिता मंत्रालय, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), [आत्मनिर्भर भारत](#)

मेन्स के लिये:

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न कषेत्रों में विकास हेतु हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने [प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ](#) (Primary Agricultural Credit Societies- PACS) की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिये **आदर्श उप-नियम** तैयार किये हैं।

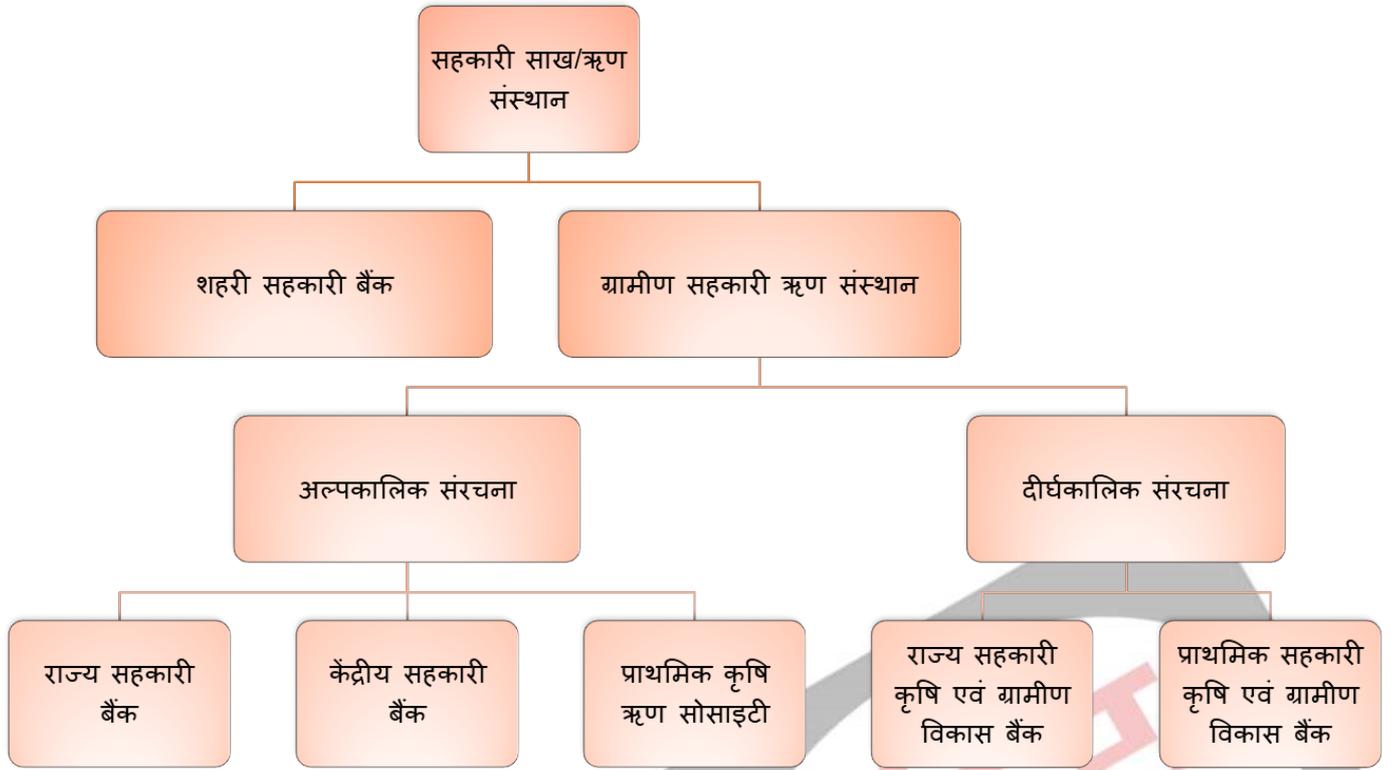
- आदर्श उप-नियम का आशय ज़मीनी स्तर पर PACS के कामकाज एवं संचालन को नयित्तरि करने के लिये सहयोग मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए दिशा-निर्देशों अथवा वनियमों के एक समूह से है।

आदर्श उपनयम का उद्देश्य क्या है?

- उपनयमों को **PACS** की संरचना, गतिविधियों और कामकाज की रूपरेखा तैयार करने के लिये **अभिकल्पित** किया गया है, जिसका उद्देश्य उनकी **आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाना** एवं ग्रामीण कषेत्रों में उनकी **भूमिका का वस्तितार** करना है।
- आदर्श उपनयम PACS को डेयरी, मत्स्यपालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज की खरीद, LPG/CNG/पेट्रोल/डीज़ल वितरण और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, **उचित मूल्य की दुकानें**, सामुदायिक सचिाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियाँ, सामान्य सेवा केंद्र आदि अल्पकालिक सहति 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में वविधिता लाने में सक्षम बनाएंगे।
- महिलाओं और **अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजातियों** को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए **PACS** की **सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के प्रावधान** किये गए हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ क्या हैं?

- **परिचय:**
 - PACS **ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियाँ** हैं जो राज्य स्तर पर **राज्य सहकारी बैंकों (State Cooperative Banks- SCB)** की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
 - SCB से ऋण का अंतरण ज़िला **केंद्रीय सहकारी बैंकों (District Central Cooperative Banks- DCCB)** को किया जाता है, जो ज़िला स्तर पर कार्य करते हैं। ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक PACS के साथ काम करते हैं, साथ ही ये सीधे किसानों से जुड़े हैं।
 - PACS विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों हेतु किसानों को **अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण** प्रदान करते हैं।
 - **प्रथम PACS वर्ष 1904 में बनाई गई थी।**



//

■ स्थिति:

- भारतीय रज़िर्व बैंक की दसिंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 1.02 लाख PACS थे। हालाँकि उनमें से केवल 47,297 मार्च 2021 के अंत तक लाभ की स्थिति में थे।

■ PACS का महत्त्व:

- PACS लघु किसानों को ऋण तक पहुँच प्रदान करती है, जिसका उपयोग वे अपने खेतों के लिये बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदने के लिये कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादन में सुधार करने एवं अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
- PACS अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति होती हैं, जो किसानों हेतु सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाती हैं।
- PACS में कम समय में न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई के साथ ऋण देने की क्षमता है।

PACS से संबंधित क्या मुद्दे हैं?

■ अपर्याप्त कवरेज:

- हालाँकि भौगोलिक रूप से सक्रिय PACS 5.8 लाख गाँवों में से लगभग 90% को कवर करती हैं लेकिन देश के कुछ हिस्से, विशेषकर पूर्वोत्तर में यह कवरेज बहुत कम है।
- इसके अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल ग्रामीण आबादी सभी ग्रामीण परिवारों का केवल 50% है।

■ अपर्याप्त संसाधन:

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक तथा मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में PACS के संसाधन अपर्याप्त हैं।
- इन अपर्याप्त नधियों का बड़ा हिस्सा उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से आता है, न कि समितियों के स्वामित्व वाले नधि अथवा उनके द्वारा एकत्रित धन के माध्यम से।

■ अतदिय और NPAs:

- अधिक मात्रा में बकाया राशि (अतदिय) PACS के लिये एक बड़ी समस्या बन गई है।
 - RBI की रिपोर्ट के अनुसार, PACS ने 1,43,044 करोड़ रुपए के ऋण तथा 72,550 करोड़ रुपए के NPA की सूचना दी थी। महाराष्ट्र में PACS की संख्या 20,897 है जिनमें से 11,326 घाटे में हैं।
- वे ऋण योग्य नधियों के संचालन पर अंकुश लगाते हैं, समाजों की उधार लेने के साथ-साथ उधार देने की शक्ति को कम करते हैं तथा ऋण चुकाने में अक्षम लोगों की एक नकारात्मक छवि बनाते हैं।

आगे की राह

- एक सदी से भी अधिक पुराने इन संस्थानों को नीतगित प्रोत्साहन मलिना चाहिये और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत सरकार के **आत्मनिर्भर भारत** के साथ-साथ वोकल फॉर लोकल के वज़िन में प्रमुख स्थान बना सकते हैं, क्योंकि इनमें एक आत्मनिर्भर गाँव की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाने की क्षमता है।
- PACS ने ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है तथा भविष्य में और भी बड़ी भूमिका नभाने की क्षमता रखती है। इसके लिये PACS को अधिक कुशल, वित्तीय रूप से सतत् और किसानों के लिये सुलभ बनाए जाने की आवश्यकता है।
- साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये नियामक ढाँचे को मज़बूत किया जाना चाहिये कि PACS प्रभावी रूप से शासति हों और किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हों।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण परदिान करने के संदर्भ में ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचित वाणजियकि बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।
2. DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमकि कृषि साख समतियिों को नधि उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. उनका पर्यवेक्षण और वनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापति स्थानीय बोर्डों द्वारा कयिा जाता है।
2. वे इक्वटि शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिग वनियमन अधनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- **सहकारी बैंक** वित्तीय संस्थाएँ वे हैं जो इसके सदस्यों से संबंधति हैं, जो एक ही समय में अपने बैंक के मालकि और ग्राहक होते हैं। वे राज्य के कानूनों द्वारा स्थापति हैं।
- भारत में सहकारी बैंक, सहकारी समति अधनियम के तहत पंजीकृत हैं। वे आरबीआई द्वारा भी वनियमति होते हैं और बैंकिग वनियम अधनियम, 1949 तथा बैंकिग कानून (सहकारी समतियिों) अधनियम, 1955 द्वारा शासति होते हैं।
- सहकारी बैंक उधार देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। वे कृषि एवं संबद्ध गतविधियिों के वतितपोषण तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों के वतितपोषण के उद्देश्य से स्थापति कयि गए हैं।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष नकिय है।
- शहरी सहकारी बैंकों का वनियमन और पर्यवेक्षण एकल-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समतियिों के राज्य रजसि्टरार तथा बहु-राज्य मामले में सहकारी समतियिों के केंद्रीय रजसि्टरार (सीआरसीएस) द्वारा कयिा जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- बैंकिग संबंधी कार्य जैसे- नए बैंक/शाखाएँ शुरू करने के लिये लाइसेंस जारी करना, 1966 में संशोधन के बाद बैंकिग वनियमन अधनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत ब्याज दरों, ऋण नीतियिों, नविशों एवं वविकपूरण जोखमि मानदंडों से संबंधति मामलों का वनियमन और पर्यवेक्षण रज़िर्व बैंक द्वारा कयिा जाता है। **अतः कथन 3 सही है।**
- भारतीय रज़िर्व बैंक ने प्राथमकि शहरी सहकारी बैंकों को इक्वटि शेयर, अधमिानी शेयर और ऋण लखित जारी करने के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की अनुमतदिते हुए मसौदा दशिा-नरिदेश जारी कयि।
 - शहरी सहकारी बैंक, सदस्यों के रूप में नामांकति अपने परचालन क्षेत्र के वयक्तियिों को इक्वटि जारी करके और मौजूदा सदस्यों को अतरिकित इक्वटि शेयरों के माध्यम से शेयर पूंजी जुटा सकते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

◦ अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसोटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग कयि जा सकता है?" (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/primary-agricultural-credit-societies-2>

